मुख्यमंत्री

डॉ. मोहन यादव

का

स्वतंत्रता दिवस संदेश

भोपाल 15 अगस्त, 2024

मेरे प्रिय भाइयो और बहनो,

78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और मंगलकामनाएँ। आज का पावन दिन भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीरों, राष्ट्रभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के पुण्य-स्मरण का अवसर है। प्रशासन जनोन्मुखी हो, नागरिक विकास और सामाजिक सद्भाव में भागीदार बनें, गरीबों के कल्याण की योजनाएँ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। पिछला एक दशक भारत के गौरव को बढ़ाने वाला गौरवशाली युग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से वैभवशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारत की अर्थव्यवस्था में मध्यप्रदेश की 4 प्रतिशत सहभागिता को अगले पाँच वर्ष में 5 प्रतिशत तक ले जाने के लिए मध्यप्रदेश संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। मध्यप्रदेश के नागरिक सदैव विकास की ललक और राष्ट्र के लिए प्रेम का परिचय देते रहे हैं।

जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं...

मध्यप्रदेश का बजट अगले पाँच वर्ष में दो गुना करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। विगत तीन वित्तीय वर्षों में राज्य शासन द्वारा अधोसंरचनात्मक पूंजीगत कार्यों के व्यय में निरंतर वृद्धि प्राप्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय 60 हजार 689 करोड़ रुपये किया गया। वर्ष 2022-23 की तुलना में यह वृद्धि लगभग 29 प्रतिशत है। राज्य शासन द्वारा एक वित्तीय वर्ष में यह अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 64 हजार 738 करोड़ रुपये रखा गया है।

भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश के शिक्षण अधिगम और इंदौर के बायो सीएनजी संयंत्र का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। साथ ही, आर्थिक सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश से संबंधित कई विषयों को शामिल किया गया है, उनमें दलहन उत्पादन, नदी जोड़ो अभियान, सोयाबीन उत्पादन, चना और गेहूँ के उत्पादन में प्रदेश के अग्रणी होने की उपलब्धि आदि शामिल हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास में चार वर्गों यथा युवा, महिला, किसान और गरीब को आधार स्तम्भ के रूप में परिभाषित किया है। मध्यप्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रेरणा लेकर चार मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवम्बर से लागू करने जा रही है।

युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, रोज़गार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्ययोजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन, स्व-रोज़गार योजनाएँ, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य करेगा।

नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य करेगी। किसानों को राहत एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे।

युवा शक्ति मिशन युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल और सशक्त बनाने का संकल्प है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, "उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।" यह समय है जब आप अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपने आत्म-विश्वास को पहचाने और इस देश को नई ऊँचाइयों तक ले जाएं।

हमारे युवाओं को सिर्फ पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि ए.आई., मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी उभरती तकनीकों की भी शिक्षा प्राप्त करनी है। इसके लिए हमने 485 करोड़ रुपये का निवेश किया है। प्रदेश के 55 जिलों के महाविद्यालयों को एक-एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया है। इन कॉलेजों में संस्कृत, बायोटेक्नोलॉजी और कम्प्यूटर साइंस जैसे नए विषयों को जोड़ा गया है। साथ ही, हमने 35 नए व्यावसायिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है, ताकि हमारे युवा न केवल शिक्षा प्राप्त करें, बल्कि रोज़गार के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो सकें।

सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से कार्य किया गया है और विगत आठ महीनों में शासकीय नौकरी के 11 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। राज्य में 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 60 से अधिक नई उद्योग इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिनसे 17 हजार से अधिक रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे।

कौशल विकास को राज्य शासन ने प्राथमिकता पर रखा है। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में 8 हजार चयनित प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया है, ताकि वे अपने कौशल को और निखार सकें और बेहतर रोज़गार के अवसर प्राप्त कर सकें।

इस वर्ष भारत सरकार के बजट में भी सीखो-कमाओ योजना की तर्ज पर इंटर्नशिप कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश में 22 नई आईटीआई की स्थापना की गयी है, जिनसे 5 हजार 280 सीटों की वृद्धि होगी। देवास, छिंदवाड़ा और धार में ग्रीन स्किलिंग आईटीआई स्थापित किए गए हैं, जहाँ सोलर टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हमने 6 प्रमुख विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए हैं। प्रदेश के स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए 50 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह कदम न केवल युवाओं के नवाचार को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित करने में मदद करेगा।

पेरिस ओलंपिक में प्रदेश के पाँच खिलाड़ियों की भागीदारी से प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश की खेल अकादमियों के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 37 स्वर्ण, 18 रजत, 15 कांस्य, इस तरह कुल 70 पदक और राष्ट्रीय स्तर पर 690 पदक जीतकर प्रदेश की शान बढ़ाई है। प्रदेश को स्पोर्ट्स हब बनाने और खेलों के माध्यम से पर्यटन विकास के प्रयास शुरू किए गए हैं।

पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य मध्यप्रदेश के युवा खिलाड़ी विवेक सागर को प्रदेश का गौरव बढ़ाने पर 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की बड़ी भूमिका है। युवा भविष्य हैं, युवा ही देश और समाज के निर्माता हैं, और युवाओं के संकल्प, मेहनत और सोच ही इस देश को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएगी।

गरीब कल्याण मिशन के माध्यम से प्रदेश ने गरीब और कमजोर वर्गों के युवाओं के जीवन में एक नया अध्याय लिखने का संकल्प लिया है। यह मिशन एक व्यापक अभियान है, जो हमारे समाज के सबसे वंचित तबके को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए समर्पित है।

हमारी सरकार मानती है कि गरीब व्यक्ति को गरीबी के चक्रव्यूह से निकालकर उन्हें एक सम्मानित और सुरक्षित जीवन प्रदान करना हमारा मुख्य ध्येय है। हम मानते हैं कि जब तक समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा, तब तक प्रदेश का वास्तविक विकास अधूरा है। इसलिए, हम इस मिशन के तहत गरीबों के जीवन-स्तर को सुधारने, उन्हें रोज़गार और स्व-रोज़गार के अवसर देने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बुनियादी सुविधाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं।

प्रदेश सरकार ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया है। प्रदेश में स्वामित्व योजना के माध्यम से 23 लाख 50 हजार लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और आत्म-निर्भर बन सकें। इस योजना के अंतर्गत 24 हजार से अधिक ग्रामों का डाटा एकत्र कर 24 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं। प्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत, 30 हजार 500 से अधिक श्रमिक परिवारों को 670 करोड़ रुपये से अधिक की अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण किया गया है।

मजदूरों की दिव्यांगता और मृत्यु के आधार पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही, प्रदेश सरकार अब श्रमिकों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी देने जा रही है। शहरी क्षेत्र के निर्धन वर्ग के नागरिकों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित है। इसी तरह लघु व्यवसाय करने वाले भाइयों के आर्थिक उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना संचालित है। इन दोनों योजनाओं का मध्यप्रदेश में सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन हुआ है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रदेश के 7 लाख 50 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है। पीएम जन मन योजना में विशेष पिछड़ी जनजातियों - बैगा, सहरिया और भारिया के परिवारों को भी पक्का आवास देने की शुरुआत की गई है। मध्यप्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में प्रथम है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवॉर्ड की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्र में 9 लाख 51 हजार आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 7 लाख 91 हजार आवासों का कार्य पूरा किया जा चुका है।

प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह सहायता योजना में वर्ष 2023-24 में 62 हजार 583 कन्याओं के विवाह के लिए सहायता राशि दी है। समाज के वरिष्ठजन, दिव्यांगजन, निराश्रितों और कल्याणी बहनों को प्रत्येक माह 600 रुपये दिए जा रहे हैं। अन्य तरह के 81 हजार दिव्यांगजनों को बीते वर्ष 500 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। बीते वर्ष 34 हजार दिव्यांगजनों को 43 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत के 66 हजार से अधिक कृत्रिम अंग लगवाए गए हैं।

श्रम कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं में 7 लाख श्रमिकों को 43 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। श्रमिक के परिवारों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार, विवाह सहायता, कल्याणी सहायता, श्रमिक साहित्य पुरस्कार और उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना लागू की गई है। प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से 4 आवासीय श्रमोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में संचालित इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक के 3 हजार 500 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। श्रम आयुक्त संगठन द्वारा अनेक सेवाएँ समय-सीमा में प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश के तीन औद्योगिक नगरों जबलपुर सतना और मंडीदीप में मजदूरों के लिए नवीन अस्पताल प्रारंभ होंगे।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जरूरतमंद ग्रामीणों को रोज़गार देने, अमृत सरोवर योजना, जल गंगा संवर्धन अभियान, पुष्कर धरोहर अभियान में अनेक कार्य चल रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में वर्ष 2025 तक प्रदेश के ग्रामों को कचरे और कीचड़ से मुक्ति दिलवाकर उन्हें मॉडल श्रेणी का ओडीएफ प्लस ग्राम बनाने का लक्ष्य है। करीब 42 हजार ग्रामों में यह कार्य हो गया है। इसी तरह साढ़े 8 लाख शौचालय विहीन घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 66 हजार से भी अधिक परिवारों को आर्थिक उन्नयन गतिविधियों से जोड़ा गया है। मिशन के माध्यम से सिंगरौली जिले में संचालित कोदो-कुटकी प्र-संस्करण इकाई से 20 हजार समूह सदस्य लाभान्वित होंगे।

जनजातीय वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए इस वित्त वर्ष में 40 हजार 804 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 23.4% अधिक है। तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3 हजार रुपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपये कर दिया गया है, जिसका सीधा लाभ लगभग 35 लाख संग्राहकों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना में प्रदेश में बहुउद्देशीय केंद्र, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा एवं विद्युतीकरण कार्यों पर इस वर्ष 1 हजार 607 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से अधोसंरचना के कार्य किए जा रहे हैं, जो सीधे 11 लाख से अधिक भाई-बहनों के जीवन को प्रभावित करेंगे।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रदेश के 7 हजार 300 से अधिक जनजातीय बहुल ग्रामों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और कौशल विकास के कार्य हो रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों की बहनों के खातों में जनवरी से लेकर अब तक 148 करोड़ रुपये से अधिक की आहार अनुदान राशि अंतरित की गई है। इस वित्त वर्ष में जनजातीय वर्गों के विद्यार्थियों को 728 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। छात्रावासों के विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण एवं मार्गदर्शन के लिए 24x7 मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। अब छात्रावासों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर की शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में 27 हजार 900 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, गणवेश, छात्रावास सुविधा आदि के लिए 1 हजार 427 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के बालकों की स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 1 हजार 550 रुपये और बालिकाओं की स्कॉलरशिप राशि को बढ़ाकर 1 हजार 590 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत, इस वित्तीय वर्ष में 3 हजार 500 करोड़ रुपये के व्यय से 20 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा।

हमारी रणनीति स्पष्ट और संकल्पित है - हर गरीब और कमजोर व्यक्ति को समृद्धि और सुरक्षा की ओर ले जाना। हम न केवल योजनाएँ बना रहे हैं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं।

"अंधेरा चाहे कितना भी घना हो,
उम्मीद का एक दीपक सब बदल सकता है।"

नारी सशक्तिकरण मिशन केवल एक सरकारी प्रयास नहीं, बल्कि सभी बहनों के सशक्तिकरण का एक दृढ़ संकल्प है। यह मिशन महिलाओं के सशक्तिकरण, समानता के अवसर, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है।

मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब तक प्रदेश की बहनें आत्म-निर्भर और सशक्त नहीं होंगी, तब तक समग्र विकास संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक सशक्तिकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है।

नारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत, हम बहनों को उद्यमिता में बढ़ावा देने, कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने और शिक्षा व रोज़गार के साधनों को सुलभ कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हर बहन को यह अवसर मिलेगा कि वह अपने सपनों को साकार कर सके और आत्म-निर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सके।

प्रदेश में वर्तमान में कार्य कर रहे महिला स्व-सहायता समूहों से भी बढ़ी संख्या में बहनें जुड़ी हैं। महिला स्व-सहायता समूहों को सुदृढ़ कर महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति भी प्रदेश सरकार पूरी तरह सजग है। हम स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार कर रहे हैं, बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ अभियान को और मजबूत बना रहे हैं और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू कर रहे हैं।

"लाड़ली बहना योजना" का उद्देश्य हर बहन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे किसी भी कठिनाई का सामना अपने दम पर कर सकें। अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और आत्म-निर्भर बन सकें। योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खातों में विगत आठ महीनों में 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है।

इस वर्ष, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर, प्रदेश सरकार ने हर बहन के खाते में 250 रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की है, ताकि सभी बहनें त्योहार को खुशी और सम्मान के साथ मना सकें। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई-बहन के अटूट प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर बहन की रक्षा के लिए न केवल उसका भाई, बल्कि उसकी सरकार भी सदैव तत्पर है।

"नारी तू है शक्ति रूपा, तेरे बिन सब अधूरा,

तेरी मुस्कान में बसता है, समाज का हर सपना पूरा

मिशन नारी शक्ति से होगी, तेरी नयी पहचान,

हर कदम पर तेरे संग है, सरकार का मजबूत मान"

मध्यप्रदेश महिला कल्याण के कार्यों में अग्रणी है। हमारी बहनों के आर्थिक उन्नयन के लिए बहुत-सी योजनाएँ चल रही हैं। प्रदेश प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में प्रथम है। इस योजना में 2017 से 2024 तक 41 लाख 70 हजार बहनों को 1 हजार 150 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। महिला स्व-सहायता समूहों को 9 हजार 560 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता उपलब्ध करायी गई है। उच्च शिक्षा में प्रवेश पर 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।

हर महीने 117 लाख पात्र परिवारों को नि:शुल्क अनाज प्रदाय किया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से बहनों को रसोई गैस सुविधा दिलवाकर उनको धुंए से होने वाले कष्ट से मुक्ति दिलवाई है। मध्यप्रदेश में लगभग 90 लाख बहनों को गैस कनेक्शन दिया गया है। प्रदेश की 45 लाख 89 हजार बहनों के खातों में 450 रुपये में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए 118 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है।

मध्यप्रदेश में स्त्री-पुरुष अनुपात में सुधार हुआ है। यह अनुपात प्रति एक हजार पुरुषों पर 927 महिलाओं से बढ़कर 956 हो चुका है। प्रदेश में 453 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 84 हजार 659 आँगनवाड़ी केन्द्र और 12 हजार 670 मिनी आँगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा-अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 194 नए आँगनवाड़ी केन्द्र प्रारंभ किए गए हैं।

किसान कल्याण मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, जो किसान भाइयों और बहनों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और प्रदेश की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएंगे। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और अन्नदाताओं की मेहनत और परिश्रम से ही हमारा समाज फल-फूल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों की उपज की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आधुनिक तकनीकी साधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि को लाभदायी व्यवसाय बनाने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण प्रदाय करने की योजना को निरंतर रखा जाएगा। इस साल 23 हजार करोड़ रुपये का फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लाखों किसान भाई लाभान्वित होंगे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना के तहत अब तक 80 लाख से अधिक किसान भाइयों के खातों में 1 हजार 643 करोड़ रुपये का अंतरण किया है। हमारा उद्देश्य किसानों की आमदनी को दोगुना करना है और इसके लिए सिंचाई की क्षमता बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने और कृषि जिन्सों के निर्यात को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सरकार ने फसलों की उपार्जन व्यवस्था और मंडियों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। साथ ही, आईटी और एआई जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके खेती के कामों को आसान और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मिट्टी परीक्षण में कृषि स्नातक युवाओं के साथ पार्टनरशिप में कार्य करने की नीति बनाई गई है।

कृषि प्र-संस्करण उद्योगों का जाल बिछाकर स्थानीय स्तर पर ही कृषि उपज का मूल्य संवर्धन करने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके तहत प्र-संस्करण इकाई स्थापित करने के लिए बजट बढ़ाया जाएगा।

मध्यप्रदेश देश के कुल दलहन उत्पादन का एक चौथाई हिस्सा उत्पादित कर भारत में प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन उत्पादन में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है। चना और गेहूँ के उत्पादन में भी मध्यप्रदेश प्रथम है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्यप्रदेश, देश में द्वितीय स्थान पर है।

मक्का, मोटे अनाज, मूंगफली और मटर के उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। देश के कुल तिलहन उत्पादन में मध्यप्रदेश का पाँचवां हिस्सा है। इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के सभी किसान भाई बधाई के पात्र हैं।

प्रदेश में इस वित्त वर्ष में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 66 हजार 605 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वर्तमान में लगभग 32 लाख से अधिक कृषक शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 4 हजार 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना अंतर्गत 80 लाख से अधिक किसानों के खातों में अब तक 12 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक का अंतरण किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इस वित्त वर्ष में 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। खरीफ-23 के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा किसानों को 750 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के दावों का भुगतान किया गया है। पहली बार प्रदेश में किसानों के लिए ऋण की अदायगी की अंतिम तिथि (28 मार्च) से पहले सरकार ने दावों का भुगतान कर किसानों को अनावश्यक ब्याज भरने के दण्ड से बचाया है।

प्रदेश सरकार ने श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है। योजना में किसानों को प्रति क्विंटल एक हजार रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये के बोनस भुगतान के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में 6 लाख से अधिक किसानों से 48 लाख 35 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा चुका है।

मध्यप्रदेश संतरा, धनिया, लहसुन और मसाला उत्पादन में देश में प्रथम और समग्र रूप से उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में देश के शीर्ष तीन राज्यों में शामिल है। प्रदेश में संभाग स्तर पर 10 नर्सरियों को हाइटेक बनाने की कार्यवाही की जा रही है और उनके कुशल प्रबंधन के लिए पोर्टल बनाया गया है।

मध्यप्रदेश "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने के लिए कृत-संकल्पित है। प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में 53 हजार सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान का कार्य हो रहा है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों और उनसे जुड़ी पैक्स समितियों के माध्यम से 40 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं।

खरीफ सीजन 2024 में विपणन संघ ने 10 लाख मीट्रिक टन उर्वरक बाँटे हैं। उत्पादकता और सकल उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रचुर मात्रा में उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 1 हजार 711 पंजीकृत प्राथमिक बीज सहकारी संस्थाएँ सक्रिय हैं। प्रदेश में 2 हजार 725 पैक्स संस्थाओं में सामान्य सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। सहकारी क्षेत्र में कृषक उत्पादक समूहों का गठन भी किया गया है।

मध्यप्रदेश में उपलब्ध कुल जल क्षेत्र 4 लाख 42 हजार हेक्टेयर में से 4 लाख 40 हजार हेक्टेयर जल क्षेत्र अर्थात 99 प्रतिशत में मत्स्य- पालन हो रहा है। मत्स्य-उत्पादन में 3 लाख 90 हजार मीट्रिक टन के लक्ष्य की तुलना में 3 लाख 82 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य-संपदा योजना भी लागू की गई है।

प्रदेश के पश्चिम अंचल की तुलना में पूर्वी क्षेत्र के जिलों में कम दुग्ध उत्पादन के असंतुलन को दूर कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ करारनामा किया गया है। पशुपालकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। योजना में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर पशुपालन, गौ-पालन और डेयरी विभाग किया जा रहा है। पशुपालन विकास योजना में 14 जिलों के विशेष पिछड़ी जनजाति के पशुपालकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर दुधारू पशु दिलवाने की पहल की गई है।

प्रदेश में संचालित 2 हजार 190 गौ-शालाओं में लगभग 3 लाख गौ-वंश का पालन हो रहा है। प्रदेश में भारतीय नव वर्ष इस चैत्र माह से अगले वर्ष तक गौ-वंश रक्षा वर्ष मनाया जा रहा है।

गौ-शालाओं में पशु आहार योजना पर इस वर्ष 250 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। मध्यप्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि देगी, जिसका लाभ दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को मिलेगा।

अच्छी सड़कें प्रदेश के विकास को गति प्रदान करती हैं। प्रदेश में 6 एक्सप्रेस-वे परियोजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। वर्ष 2024-25 में 5 हजार 100 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण किया जाएगा। जबलपुर और भोपाल में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे निर्माण के लिए 5 हजार 17 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है।

इस मार्ग के निर्माण से उज्जैन, इंदौर एवं आस-पास के क्षेत्र मुम्बई-दिल्ली 8-लेन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (एक्सप्रेस-वे) से जुड़ जाएंगे। लोक पथ मोबाइल एप प्रारंभ किया गया है, जिससे नागरिक सड़कों की मरम्मत के लिए सीधे जिम्मेदार अधिकारी तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस वित्त वर्ष में 900 किलोमीटर से अधिक लम्बाई की सड़कें बन गई हैं। इस योजना में पर्यावरण की अनुकूलता की दृष्टि से नई तकनीक से वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल कर करीब डेढ़ हजार किलोमीटर लम्बे मार्गों का निर्माण एवं 1 हजार 440 किलोमीटर मार्ग का नवीनीकरण करवाया गया है।

प्रदेश में कुल 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में वर्ष 2028-29 तक सिंचाई क्षमता को 1 करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सिंचित रकबा बढ़ाने और पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश राज्य की केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों के 1 हजार 900 ग्रामों में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, 41 लाख की आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी और 150 मेगावॉट विद्युत का उत्पादन भी होगा। राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्य की पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है, जिसका लाभ प्रदेश के 10 जिलों को मिलेगा।

इस परियोजना से मालवा-चंबल क्षेत्र में 4 लाख 48 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए 80 हजार करोड़ रुपये की लागत से 101 परियोजनाओं में दाब युक्त पाइप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। नर्मदा घाटी परियोजनाओं से लगभग 26 लाख हेक्टेयर भूमि में नवीन सिंचाई क्षमता निर्मित हुई।

मध्यप्रदेश विद्युत उपलब्धता में वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप आत्म-निर्भर हो गया है। प्रदेश की उपलब्ध विद्युत क्षमता 22 हजार 823 मेगावॉट है। भविष्य में भी विद्युत के क्षेत्र में प्रदेश आत्म-निर्भर बना रहे इसके लिए उपलब्ध विद्युत क्षमता में 3 हजार 315 मेगावॉट की वृद्धि का कार्यक्रम है, जिसमें से 510 मेगावॉट की क्षमता वृद्धि की जा चुकी है। गैर-कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत प्रदाय की जा रही है। प्रदेश में पारेषण हानियाँ अब मात्र 2.61 प्रतिशत रह गई हैं, जो पूरे देश में न्यूनतम हानियों में शामिल हैं।

प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं एवं कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए क्रमश: अटल गृह ज्योति योजना एवं अटल कृषि ज्योति योजना लागू है। अटल कृषि ज्योति योजना के 10 हॉर्सपावर तक के अनमीटर्ड स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 750 रुपये प्रति हॉर्सपावर प्रतिवर्ष एवं 10 हॉर्सपावर से अधिक के अनमीटर्ड स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 1 हजार 500 रुपये प्रति हॉर्सपावर प्रतिवर्ष की फ्लेट रेट दर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

अटल गृह ज्योति योजना में प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक है। योजना में 100 वॉट तक के संयोजित भार के 30 यूनिट की मासिक खपत वाली उपभोक्ता श्रेणी एल व्ही-1.1 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 25 रुपये का बिल दिया जा रहा है और अंतर की राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में दे रही है।

प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता दस साल पहले मात्र 438 मेगावॉट थी, जो अब बढ़कर कुल 6 हजार 444 मेगावॉट हो गई है, आगर सौर पार्क की स्थापना का कार्य अप्रैल 2024 में पूर्ण कर लिया गया है। ओंकारेश्वर में सौर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ हो गया है। अन्य स्थानों जैसे नीमच, आगर-मालवा और रीवा में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने एवं किसानों के हित में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तीनों घटक लागू किए गए हैं। पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली में कमजोर वर्ग के घरों पर सोलर संयंत्रों की स्थापना के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है।

प्रदेश के 71 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर में जल-प्रदाय की सुविधा प्रदान की गई है। प्रदेश के 14 हजार 636 ग्रामों के समस्त घरों में नल से जल पहुँचाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 64 प्रतिशत ग्रामीण परिवार पेयजल की यह सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश के दो जिलों बुरहानपुर और निवाड़ी में यह कार्य शत-प्रतिशत हो गया है।

ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन और संधारण में गाँव के ही नौजवानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जरूरी प्रशिक्षण भी दिलवाया जा रहा है। खुले बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने से उनकी मौत पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में अधिनियम लागू किया गया है।

प्रदेश के औद्योगिक विकास की ठोस पहल के रूप में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखला प्रारंभ हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में 535 एमएसएमई एवं वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को 622 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इनमें कुल 14 हजार 853 करोड़ रुपये के निवेश से 33 हजार से अधिक लोगों को रोज़गार मिलने जा रहा है। प्रदेश में 31 नए औद्योगिक क्षेत्रों को कुल 9 हजार 800 एकड़ भूमि प्रदान की जा रही है। इनमें दो आई.टी. पार्क भी शामिल हैं। प्रदेश में 12 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में 382 करोड़ की लागत से उन्नयन कार्य किए जा रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना का निर्णय महत्वपूर्ण है, जिसमें 38 इकाइयों को 95 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। प्रदेश में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए भी पहल हुई है। मुरैना में मेगा लेदर पार्क विकसित करने का कार्य हो रहा है।

प्रदेश में टेक्सटाईल क्षेत्र में निरंतर निवेश के दरवाजे खुल रहे हैं। धार में "पीएम मित्र इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाईल पार्क" से कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी। यहाँ 1 हजार 563 एकड़ भूमि पर एक हजार करोड़ की लागत से पार्क विकसित होगा, जो तीन लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार देगा। राज्य सरकार ने एक निर्यात प्रोत्साहन सेल भी बनाया है।

वर्तमान में प्रदेश से फार्मा उत्पाद, कॉटन यार्न और खाद्य उत्पाद का निर्यात हो रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर किसी भी व्यवसाय, उद्योग की स्थापना के लिए निवेशकों को विशेष सुविधा प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां विदेशों में जाती हैं। इसी तरह वारासिवनी, सौंसर और पड़ाना-सारंगपुर के हाथकरघा वस्त्र विशिष्ट पहचान रखते हैं। वस्त्र छपाई में बाघ की ब्लाक प्रिंट और भैरोगढ़ की बटिक प्रिंट की भी दूर-दूर तक मांग है।

हमारे ग्रामीण भाई और शहर के भी ऐसे हुनरमंद कारीगर जिनके रोज़गार का साधन बुनाई और कसीदाकारी है, के आर्थिक उन्नयन के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। पचमढ़ी के शासकीय रेशम केन्द्र में सिल्कटेक पार्क की स्थापना की गई है। मालाखेड़ी रेशम केन्द्र को प्रमुख निर्यात केन्द्र बनाने की पहल हुई है। शिल्पियों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया जा रहा है। कुछ शिल्पों के लिए जी.आई. प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किए गए हैं, जिनमें उज्जैन के बटिक शिल्प, जबलपुर का पत्थर शिल्प, ग्वालियर का हैण्डमेड कार्पेट और वारासिवनी की हैण्डलूम साड़ी शामिल है।

मध्यप्रदेश खनिज संपदा के मामले में समृद्ध है। प्रदेश में मुख्य खनिज की 718 खदानें स्वीकृत हैं। प्रदेश का हीरा खनन कार्य पूरे देश में अनूठा है। भविष्य में प्रदेश में हीरा तराशने का कार्य भी किया जाएगा। खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत भोपाल में तीन चेक गेट लगाए जा रहे हैं। एआई तकनीक के उपयोग से संपूर्ण प्रदेश में शीघ्र ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

प्रदेश में व्यावसायिक खनन के लिए 27 कोल ब्लॉक मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 6 कार्यशील हो चुके हैं। खनिज निगम में प्रदेश के 42 जिलों में 44 रेत समूहों की रेत उत्खनन और विक्रय की ई-निविदा सह-नीलामी की कार्यवाही की गई। इससे सालाना 1100 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व की प्राप्ति की संभावना है। नदियों से प्राकृतिक रेत की निर्भरता को कम कर पत्थर से निर्मित रेत (एम सेंड) को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रदेश में रेत खनिज के अलावा रॉक फॉस्फेट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, फर्शी पत्थर, पायरोफिलाइट और ग्रेनाइट खनिज के क्षेत्र में भी कार्य किए जा रहे हैं। पट्टेदारों और नागरिकों की समस्या के ऑनलाइन निराकरण के लिए नया पोर्टल शुरू किया जाएगा।

नमामि गंगे सदानीरा कार्यक्रम में प्रदेश की सभी जल-संरचनाओं को फिर से उपयोगी बनाने और उनके संवर्धन के लिए मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद सैटेलाइट मैपिंग कर जिलेवार दस्तावेजीकरण का कार्य कर रही है। नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य एकल नागरिक डेटाबेस (सिंगल सिटीजन डेटाबेस) तैयार किया गया है। वर्तमान में 9 विभागों की 67 योजनाओं में एकल नागरिक डेटाबेस (समग्र आईडी) का उपयोग प्रारंभ करवाया गया है। स्टेट डाटा सेंटर शासकीय विभागों और उपक्रमों को कम्प्यूटिंग सेवाएँ प्रदान कर रहा है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 9 हजार 600 कार्यालयों को नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा चुकी है।

प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान तक जाने और अन्य नगरों के प्रवास के लिए कम कीमत पर वायुयान सेवा का लाभ नागरिकों को देना प्रारंभ किया गया है। हवाई पटिट्यों के विकास के साथ ही उज्जैन, गुना और शिवपुरी में विमानतल के विकास के लिए कार्य प्रारंभ किए गए हैं। प्रदेश में दिल्ली की तरह कार्गो हब की सुविधा विकसित की जाएगी।

शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं शिक्षा व्यवस्था को सर्व सुविधायुक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र के सहयोग से पीएमश्री योजना प्रदेश के 416 विद्यालयों में संचालित है।

इस वित्तीय वर्ष में योजना को 137 विद्यालयों में शुरू किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम चरण में 275 सीएम राइज़ विद्यालय संचालित हो रहे हैं। पिछले तीन शिक्षा सत्र में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं अन्य पदों पर कुल 32 हजार 82 शिक्षकों की भर्ती की गई है। वर्ष 2024-25 में 4 लाख 50 हजार पात्र छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी। नवीन शिक्षक आवास योजना के अंतर्गत शैक्षणिक व्यवस्था में और अधिक गुणवत्ता लाने के लिए ग्रामीण शिक्षकों के लिए आवास योजना की स्वीकृति दी गई है। कक्षा एक और दो के बच्चों के लिए राज्य सरकार ने दक्षता फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसमें निर्धारित लर्निंग आउटकम्स के आधार पर हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित की अभ्यास पुस्तिकाएँ एवं लर्निंग किट तैयार कर वितरित किए गए हैं। समग्र शिक्षा के अंतर्गत सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना में कक्षा 7 से 12 की 19 लाख छात्राओं के बैंक खातों में प्रति छात्रा 300 रुपये के मान से रुपये 57 करोड़ की राशि अंतरित की गई है ।

देश के स्वतंत्र होने के पहले, वर्ष 1946 में एक व्यक्ति के दान से सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना से मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय नक्शे पर अग्रणी राज्य बना था। इस समृद्ध अतीत के स्मरण के साथ वर्तमान में भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव कार्य हो रहा है।

मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। राज्य का वर्ष 2021-22 का सकल पंजीयक (जीईआर) अनुपात अखिल भारतीय अनुपात 28.4 की तुलना में 28.9 दर्ज हुआ है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप विश्वविद्यालय के कुलपति पद को अब कुलगुरु नाम दिया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल कर मातृ भाषाओं को महत्व दिया है। मध्यप्रदेश, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अग्रणी रहा है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) में प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना तथा अन्य विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। महाविद्यालयों के लिए 2 हजार से अधिक नवीन पद सृजित किए गए हैं। खरगोन में क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय प्रारंभ किये गये हैं। सागर में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के नाम से आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ किया जा रहा है।

शासकीय महाविद्यालयों में कृषि को एक विषय के रूप में जोड़ा गया है। विश्वविद्यालयों में पायलट ट्रेनिंग का कोर्स भी हम शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षा में गुणवत्ता के लिये भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और रीवा के 6 विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की गयी है। महाविद्यालय स्तर पर विदेशी भाषाओं के अध्ययन केन्द्र भी बनाये जाएंगे।

प्रदेश में देवास, छिंदवाड़ा एवं धार आई.टी.आई. को ग्रीन स्किलिंग आई.टी.आई. के रूप में विकसित कर सोलर टेक्नीशियन एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक पाठ्यक्रम प्रांरभ किये गये हैं।

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में इस वर्ष 61 हजार 629 मेधावी विद्यार्थियों को 450 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में 20 हजार से अधिक विद्यार्थी प्रशिक्षित किए गए हैं। योजना में फरवरी 2024 में 8 हजार चयनित प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख रुपये दिए गए हैं। मध्यप्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण का कार्य किया गया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एकीकृत किया गया है। प्रदेश में मेडिकल की शिक्षा हिंदी में देने की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आगामी 2 वर्ष में लगभग 25 हजार पदों को भरने की कार्ययोजना है। अत्यंत गंभीर चिकित्सकीय परिस्थिति में रोगी को त्वरित एवं विशेष चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता की स्थिति में देश के उच्चतम संस्थानों में त्वरित परिवहन किए जाने के लिए पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 200-250 एकड़ के क्षेत्र में मेडिकल पार्क विकसित होंगे, जिससे विभिन्न सुपर स्पेशलिटी सेवाएँ आमजन को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश के कुल 346 सामुदायिक केन्द्रों को एफ.आर.यू. में उन्नत करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किए जाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम एवं बचाव के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। समस्त आदिवासी बहुल जिलों में सिकल सेल एनीमिया की जाँच की जा रही है।

प्रत्येक जिला अस्पताल में आयुष विंग बनाया जा रहा है। प्रदेश में प्रत्येक जिला अस्पताल में आगामी 17 सितम्बर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर रेडक्रास से जन आरोग्य केन्द्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य संस्थाओं के सुचारु संचालन के लिए 46 हजार 491 नवीन पद की मंजूरी दी है। इससे स्वास्थ्य मानकों के निर्धारण और आम लोगों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में सहयोग मिलेगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना में मध्यप्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर संचालित हो रहे हैं। प्रदेश में शीघ्र ही 11 नए आयुर्वेद महाविद्यालय/चिकित्सालय प्रारंभ होंगे।

राजस्व विभाग की सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचाने के लिए इस वर्ष 15 जनवरी से 15 मार्च तक राजस्व महा-अभियान संचालित कर 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है । प्रदेश में 16 जुलाई से 30 अगस्त तक राजस्व महा-अभियान 2.0 जारी है।

प्रदेश में 15 अगस्त 2024 से ई-संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को लागू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से रजिस्ट्री पूर्णत: डिजिटल होकर डिजिटल हस्ताक्षर कर निष्पादित की जाएगी। कतिपय दस्तावजों के पंजीयन के लिए पक्षकारों को उप पंजीयक कार्यालय नहीं आना होगा। वह अपने घर बैठे ही उक्त दस्तावेज तैयार कर डिजिटली ही पंजीयन के लिए प्रेषित कर पाएंगे। यह प्रक्रिया ई-गवर्नेंस में मध्यप्रदेश को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगी। प्रदेश में जीएसटी के अंतर्गत गत आठ माह में 24 हजार 315 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण हुआ, जो गत वित्त वर्ष के इन महीनों में प्राप्त 20 हजार करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है।

प्रदेश में पिछड़े वर्ग के 7 लाख 37 हजार विद्यार्थियों को गत वित्त वर्ष में लगभग एक हजार करोड़ रुपये की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि मंजूर की गई है। विदेश में पढ़ाई के लिए भी 64 विद्यार्थियों को लगभग 14 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना में बैंकों के माध्यम से 600 विद्यार्थियों को 32 करोड़ 42 लाख रुपये की ऋण राशि वितरित की गई है।

जनजातीय वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए इस वित्तीय वर्ष में 40 हजार 804 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, आवास सहायता, विदेश में अध्ययन के लिए सहायता, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र और आकांक्षा योजना का लाभ दिलवाया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया और सहरिया के 2 लाख से अधिक परिवारों को हर महीने 1 हजार 500 रुपये की राशि पोषण आहार के लिए प्रदान की जा रही है। वर्ष 2023-24 में इस पर 323 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में प्रदेश के 7 हजार 307 ग्रामों का चयन किया गया है। इस वर्ष योजना में 238 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। पीएम जन मन योजना में प्रदेश में ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा एवं विद्युतीकरण कार्यों पर इस वर्ष 1 हजार 607 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। पारंपरिक जनजातीय शिल्पकारों को आजीविका से जोड़ने के लिए उनके हुनर को ज्योग्राफिकल इंडीकेशन अर्थात जीआई टैग दिलवाने की पहल हुई है। जनजाति क्षेत्रों में 94 सीएम राइज़ विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जनजातीय समुदायों के गौरवशाली व्यक्तियों के संग्रहालयों का विकास किया जा रहा है। जबलपुर में राजा शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह संग्रहालय का कार्य किया जा रहा है। जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा को नया स्वरूप दिया जा रहा है। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लायओवर का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से किया गया है।

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए जनसंख्या के मान से बजट का प्रावधान कर वर्ष 2024-25 में 2 हजार 387 करोड़ रुपये की राशि अनुसूचित जाति कल्याण के लिए रखी गई है। कक्षा एक से महाविद्यालय स्तर तक के लगभग साढ़े तेरह लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जा रही है।इस वर्ष से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की गई है।

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ समुदाय की जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश में नगरों में बेहतर नागरिक सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रोपॉलिटियन सिटी बनाई जाएगी। इंदौर और भोपाल में मेट्रो ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन सुविधा प्रारम्भ होने जा रही है।

सिंहस्थ-2028 के पहले ऐसी अनेक सुविधाएँ विकसित की जाएंगी जिससे श्रद्धालु आसानी से और कम समय में, कम ऊर्जा खर्च किए श्रद्धा स्थलों तक पहुँच सकें। स्मार्ट सिटी मिशन-2.0 में उज्जैन और जबलपुर स्मार्ट सिटी के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 270 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। कायाकल्प अभियान के अंतर्गत 2 हजार 500 करोड़ रुपये के निवेश से शहरों की सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है। शहरी पेयजल योजना में प्रदेश के 413 नगरीय निकाय एवं पाँच छावनी क्षेत्र में जल आवर्धन योजना पूर्ण करने के लिए वित्तीय व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। अमृत योजना 2.0 में समस्त नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। राज्य के 49 शहरों की 54 सीवेज परियोजनाओं की कार्ययोजना पर कार्य शुरू हो गया है। इससे प्रदेश की लगभग 60% शहरी आबादी लाभान्वित होगी।

इंदौर नगर को लगातार 7 वर्ष से देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव हासिल है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में देश का दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य होने का सम्मान मध्यप्रदेश ने प्राप्त किया है। प्रदेश को गत वर्ष स्वच्छता के क्षेत्र में सात राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं।

मध्यप्रदेश अब देश-दुनिया के पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य है। प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्मारक खजुराहो, सांची और भीमबेटका हैं। ग्वालियर किला सहित प्रदेश के अनेक स्थानों के किले पुरा वैभव के प्रतीक हैं।

भोपाल के आसपास अनेक पर्यटक स्थल हैं जैसे भोजपुर का शिव मंदिर, विदिशा जिले में उदयगिरि, ग्यारसपुर और उदयपुर, बैतूल जिले में कुकरू खामला, राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ चिड़ी खो, सीहोर में नर्मदा नदी के घाट, नर्मदापुरम अंचल के सुंदर स्थान जैसे पचमढ़ी और मड़ई। ओरछा और मांडव के साथ ही ग्रामीण पर्यटन के अनेक स्थान भी प्रदेश की धरोहर हैं। अनेक राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

पर्यटन के माध्यम से लघु व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिले, इस दृष्टि से पत्थर शिल्प से जुड़े कलाकारों को प्रशिक्षण दिलवाकर उनके व्यवसाय का उन्नयन किया जाएगा।

मध्यप्रदेश भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों से विक्रमोत्सव के अवसर पर दुनिया की पहली "विक्रमादित्य वैदिक घड़ी" का शुभारंभ कर भारतीय काल गणना परंपरा का साक्षात्कार पूरी दुनिया से कराया गया है। "पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा" प्रारम्भ कर प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा से जोड़ा गया है। "पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा" का संचालन भी प्रारम्भ किया गया है। भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के बिना संसार अधूरा है। भगवान श्रीकृष्ण के चरण प्रदेश के जिन स्थानों पर पड़े थे, उन स्थानों के विकास के लिए श्रीकृष्ण पाथेय योजना की कार्ययोजना बनाने का कार्य प्रगति पर है।

श्रीराम वन गमन पथ के विकास के लिए चित्रकूट पन्ना, सतना, अमरकंटक आदि स्थानों पर अनेक कार्य किए जा रहे हैं। कुल 370 किलोमीटर के पथ के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अनेक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की जा चुकी है। वीर भारत संग्रहालय स्थापित कर भारतीय सभ्यता के संरक्षकों के योगदान को सहेजा जाएगा।इस वर्ष वीरांगना रानी दुर्गावती का 500वां जयंती उत्सव और देवी अहिल्याबाई का 300वां जयंती उत्सव विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा।

गोंड चित्रकला के अग्रणी साधक स्व. जनगण सिंह श्याम की स्मृति में डिण्डोरी जिले के पाटनगढ़ में कला केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्र के प्रथम पारम्परिक कलाओं के गुरुकुल की स्थापना खजुराहो में की जाएगी। प्रदेश के नागरिकों को अपनी लोक संस्कृति, ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी और पुरा वैभव से परिचित करवाने की पहल की गई है। इस क्रम में प्रदेश के युवाओं को ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की अध्ययन यात्रा का व्यापक स्तर पर आयोजन करने की कल्पना भी साकार की जाएगी।

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में इस वर्ष से हवाई जहाज के माध्यम से तीर्थ यात्रा की शुरुआत हुई है। उज्जैन में धर्मस्व संचालनालय कार्यालय को स्थानांतरित किया गया है। विरासत के साथ विकास के विचार को महत्व देते हुए प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लोक विकसित किये जा रहे हैं।

इन लोकों में संत रविदास लोक-सागर, रानी दुर्गावती स्मारक और रानी अवंतीबाई स्मारक-जबलपुर, माँ नर्मदा महालोक-अमरकंटक, देवी अहिल्या लोक-खरगोन, नागलवाड़ी लोक-बड़वानी, देवी लोक-सलकनपुर, श्री रामराजा लोक-ओरछा, जाम साँवली श्री हनुमान लोक-पांढुर्णा, श्री पशुपति नाथ लोक-मंदसौर, अटल स्मारक- ग्वालियर, श्री परशुराम लोक-जानापाव, महाराणा प्रताप लोक-भोपाल, भादवामाता लोक-नीमच, माँ पीताम्बरा लोक-दतिया और माता मंदिर लोक-रतनगढ़ और माँ शारदा देवी-मैहर एवं माँ जागेश्वरी माता मंदिर-चंदेरी शामिल हैं। इसके अलावा उज्जैन में श्री महाकाल लोक और ओंकारेश्वर में एकात्म धाम के निर्माण एवं विकास से प्रदेश में धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटन विकास में वृद्धि हो रही है। श्री महाकाल लोक में एफआरबी प्लास्टिक प्रतिमाओं की जगह अब ठोस पत्थर की प्रतिमाएँ लगाई जाएंगी। इसके साथ ही सभी नवीन लोकों के निर्माण में भी ठोस पत्थर से मूर्तियाँ बनाई जाएंगी।

वनों और वन्य-प्राणियों ने मध्यप्रदेश की एक अलग पहचान बनाई है। मध्यप्रदेश बाघ, तेंदुआ और घड़ियाल जैसे प्राणियों की सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश है। चीता पुनर्स्थापन करने वाला मध्यप्रदेश एकमात्र प्रदेश है। हरियाली बढ़ाने के लिए 82 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पौधे लगाए जा रहे हैं।

प्रदेश में 7 टाइगर रिज़र्व विकसित किए गए हैं। रातापानी टाईगर रिज़र्व बन जाने के बाद भोपाल देश की एकमात्र टाईगर रिज़र्व राजधानी होगी। प्रधानमंत्री जी के "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत प्रदेश के शहर-शहर और गाँव-गाँव में जनता की व्यापक भागीदारी के साथ पौधे लगाए जा रहे हैं।

प्रदेशवासियों के जीवन को आनंदित बनाने के लिए आनंद संस्थान और आनंद विभाग अल्पविराम जैसे कार्यक्रम और शिविर आयोजित कर रहा है।

कानून और व्यवस्था की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में पुलिस थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का ऐतिहासिक कार्य हुआ है। प्रदेश में 627 पुलिस थानों की सीमाएँ फिर से तय की गईं, इससे 2 हजार 200 से अधिक गाँवों को लाभ मिला है। पुलिसकर्मियों को लंबित पदोन्नति प्रदान करने के लिए लागू की गई कार्यवाहक व्यवस्था से लगभग तीन हजार पुलिसकर्मी लाभान्वित हुए हैं। पुलिस बल के आवासों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा एक जुलाई से लागू नये कानूनों की जानकारी आम जनता को देने के लिए थाना स्तर पर कार्यक्रम किए गए हैं। प्रदेश में निर्धारित मापदंड से अधिक ध्वनि में लाउड स्पीकर के उपयोग पर नियंत्रण के लिए पहल की गई है। आतंकी और नक्सली तत्वों और अपराधियों पर सख्ती से नियंत्रण किया गया है।

प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड दल का प्रबंध किया गया है। साथ ही नक्सल, आतंकवाद, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गई है। प्रदेश सरकार एन्टीसोशल एलीमेंट्स को समूल नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

प्रदेश के प्रमुख नगरों में सुरक्षा संबंधी उपकरणों के लिए बजट प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश होमगार्ड को नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 18 हजार से अधिक व्यक्तियों की जीवन रक्षा की उपलब्धि अर्जित हुई है। होमगार्ड के पाँच हजार रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे।

कैदियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान करने के साथ ही टेलिमेडिसिन की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। जेलों में ई-मुलाकात की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। बंदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष 44 नए बैरेक के निर्माण से 3 हजार बंदियों की आवास क्षमता बढ़ाई गई है। भिंड, छिंदवाड़ा और इंदौर में नई जेलें बनाई जा रही हैं। प्रदेश की जेलों में परिरुद्ध बंदियों के मानसिक विकास के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार और अन्य केंद्रों द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे।

सुशासन के उद्देश्य से परिवहन जाँच चौकियों के स्थान पर वाहन चेकिंग की नवीन व्यवस्था लागू की गई है। अब राज्य स्तर के साथ संभागीय और जिला स्तर पर भी चालक प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ होंगे। प्रदेश में महिलाओं को साढ़े छह लाख ड्राइविंग लाइसेंस और साढ़े सात लाख लर्निंग लाइसेंस निःशुल्क जारी किए गए हैं। महिलाओं को हल्के मोटरयान चलाने का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

इस वर्ष हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से लोगों को न्याय पहुँचाने की नयी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में गंभीर रूप से बीमार अधिवक्ताओं को सहायता राशि प्रदान की गई है। राज्य में मुकदमों के प्रबंधन और संचालन की प्रक्रिया में सुधार की पहल की गई है।

प्रदेश में नागरिकों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 741 अधिसूचित सेवाओं का लाभ समय-सीमा में मिल रहा है। इस व्यवस्था के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर, सीएम जन-सेवा, दिव्यांग हेल्पलाइन, लोक सेवा केन्द्रों पर आधार कार्ड पंजीयन एवं सुधार सेवा, उप लोक सेवा केन्द्र और पुलिस थानों में एफ.आई.आर. की प्रति प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है।

आज आजादी की वर्षगाँठ का दिन है। यह दिन सच्चे अर्थों में आजादी के फल को नागरिकों तक पहुँचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने का दिन है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व की पाँचवीं अर्थव्यवस्था बनने के सफर को तय कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री जी के संकल्पों की सिद्धि में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मध्यप्रदेश ने पिछले वर्षों में प्रगति और विकास की यात्रा में तेजी से कदम बढ़ाये हैं। हमें अब इस यात्रा को निरंतरता देना है। प्रदेशवासियों की तरक्की और खुशहाली को देश-दुनिया के सामने मिसाल बनाना है। इसके लिए प्रदेश सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा, महिला, गरीब और किसान भाइयों के विकास और कल्याण को देश के विकास की कुंजी बताया है। प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप इन वर्गों के कल्याण के लिए युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, नारी सशक्तिकरण मिशन और किसान कल्याण मिशन बनाकर काम करने जा रही है। मुझे विश्वास है कि हम अपने कर्मठ प्रदेशवासियों की सहभागिता से ऐसा करने में सफल होंगे ।

मध्यप्रदेश समृद्ध हो, साक्षर हो, स्वस्थ हो, सबसे आगे हो, सबसे न्यारा हो, सबसे खुशहाल हो। शांति का टापू हमारा प्रदेश विकास का टापू बने, खुशहाली का सागर इसके पैर पखारे और तरक्की आरती उतारे, यही कामना है।

स्वतंत्रता का सूरज हमसे कहता,

सब मिलकर दीप जलाएँ

अंधेरे को हराने का प्रण लें,

नवयुग का निर्माण कराएँ

एक बार पुनः सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई।

जय हिन्द-जय मध्यप्रदेश

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल—2024